

likely to shut down as a result thereof; and

(b) if so, whether Government propose to meet their demand to avoid closure of these factories?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) Yes. The Government is aware that the small scale units are facing problems due to non-availability of natural raw rubber. According to census data of small scale industries, the number of rubber based units in Haryana is about one hundred only.

(b) The Government is already seized of the matter and is considering steps to resolve the problems.

M/s. Siemens Contract with B.H.E.L.

5003. SHRI RAMDEO SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) Since when M/s. Siemens contracts with BHEL was more or less finalised and the broad outlines of the arrangements arrived at during 1976 and thereafter;

(b) the technological capacity of M/s. BHEL three years ago and the programme of upgrading technology in the coming five years;

(c) whether it is a fact that there is a proposal to raise annual turnover of BHEL to 1200 crores by 1983-84; and

(d) the extent to what M/s. Siemens will get the share in profit etc., what is the present percentage BHEL is giving to them for technological agreements?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) BHEL entered into three agreements with Siemens during 1974 and 1975 and one agreement with KWU, subsidiary of Siemens in 1976. A proposal

to enter into another agreement with Siemens for a number of products and systems is under consideration.

(b) BHEL manufacture a number of products for the power and industrial field. Steps to update the technological capacity are being taken. The technology in the field of boilers, auxiliaries, compressors, etc. were kept updated and are to international standards; to upgrade technology in the area of electrical products like transformers, motors, hydro-generators etc. proposals are under consideration. Arrangements for securing improved technology for turbo sets have been made.

(c) Yes, Sir. Based on the current indications of the power programme and the growth in the industrial sector, BHEL's turnover is expected to reach Rs. 1200 crores by 1983-84.

(d) M/s. Siemens will not get any share in the profit. The collaboration proposal under consideration envisages payment of lumpsum of DM 5 million per year for ten years and a royalty of 1.8 per cent. BHEL's existing agreements with Siemens provide for a royalty payment of 4-5 per cent and for the agreement with KWU 2-4 per cent.

दूर-दर्शन की ट्रांसपोर्ट यूनिट के कार्यकरण की जांच

5004. श्री टी० एन० नेमो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दिनांक 19 जुलाई, 1978 के प्रसारित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में कितने अधिकारियों का हाथ है तथा इस मामले का व्यय क्या है ;

(ख) गत दो वर्षों में इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का उन्हें बचाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले के परिणामों को कब तक विदित करा दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण शहाबशाही) : (क) 22 फरवरी, 1978 के प्रसारित प्रश्न संख्या 302 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित 3 व्यक्तियों में से, प्रागे जॉब-इटाल के परिणाम-स्वरूप दो व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों को छोड़ दिया गया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रकार अब 7 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां चल रही हैं।

(ख) और (ग). दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध कार्रवाई प्रवृत्तासनिक कार्यवाहियों के पूरा होने पर की जाएगी। किसी भी दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों) को सरकार द्वारा बचाने का कोई प्रश्न नहीं है।

(घ) कार्यवाहियों को शीघ्र पूरा करने की प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि नियमों में निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना है।

हिन्दी के टाइपराइटरों के "की बोर्ड" में परिवर्तन

5005. श्री सुब्रह्मण्य सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी परिषद् ने हिन्दी टाइपराइटरों के वर्तमान "की बोर्ड" में परिवर्तन करने के विरुद्ध निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्तमान "की बोर्ड" में कोई खामियां हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ; तथा

(ङ) क्या समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र में टाइपराइटर बनाने का निर्णय किया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल शहाज) : (क) से (घ). केन्द्रीय हिन्दी समिति ने 26 मई, 1976 की बैठक में हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों में सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया और टाइपराइटरों को सुधारा हुआ मानक रूप देने का निर्णय किया। इसके पहले देवनागरी टाइपराइटरों के कुंजीपटल में 5 बार परिवर्तन किये जा चुके हैं। बार-बार परिवर्तन करने से टाइपिस्टों और माशुलिपिकों को त्रुटिबद्धा होती ही है, टाइपराइटर निर्माताओं को भी हानि होती है। इसलिए यह तय किया गया है कि सुधारा हुआ मानक रूप देने के बाद कुछ समय तक कुंजीपटल में कोई परिवर्तन न किया जाए। इस मुद्दे हुए नवीनतम कुंजीपटल में पिछली सभी खामियां दूर करने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस बारे में और कोई कार्रवाई करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

Incentive to Cement Industries

5006. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details offered by Government to give incentives to cement industries;

(b) whether these incentives are being offered in consultation with the Tariff Commission; and